निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
1.	डिजिटल शासन की स्थापना	शासन के कार्यो में ऑनलाइन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना	50000	मंत्रालय के समस्त विभागों में ऑनलाइन नस्ती/डाक प्रचालन	1. डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्रालय स्थापना के सभी कर्मचारीयों/अधिकारीयों के लिए शत प्रतिशत अचल संपत्ति विवरण प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल सचिवालय के माध्यम से संभव हो पाई है। इसके माध्यम से वर्ष 2019-20 में 1229 कर्मचारीयों/ अधिकारीयों ने अ,नलाइन अचल संपत्ति विवरण का संपादन किया । 2. डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्रालय स्थापना के सभी कर्मचारीयों/अधिकारीयों के लिए शत प्रतिशत वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल सचिवालय के माध्यम से संभव हो पाई है। इसके माध्यम से वर्ष 2019-20 में 3076 वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अ,नलाइन का ट्रांसेक्शन किया । 3. डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्रालय स्थापना के सभी कर्मचारीयों/अधिकारीयों के लिए शत प्रतिशत अवकाश प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल सचिवालय के माध्यम से संभव हो पाई है। इसके माध्यम से वर्ष 2019-20 में 10971 अवकाशों का अ,नलाइन का ट्रांसेक्शन किया ।	3570

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
					4. डिजिटल सचिवालय परियोजना के अंतर्गत परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.01. 2019 एवं 28.06.2020 में संपन्न हुई। उक्त बैठकों में डिजिटल सचिवालय परियोजना को वर्ष 2019-20 में 6-6 माह के 2 मगजमदेपवद प्रदान किये गए।	
2.	मुख्यमंत्री डैशबोर्ड याजना	शासन के विभागों के प्रदर्शन की समेकित समीक्षा	22800	कृषि, स्कूल शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास तथा जल संसाधन विभाग की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का विकास एवं संचालन	क्र इस परियोजना के दो भाग क्रमश: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं सलाहकार सेवाएं है। जिसमे डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय में केन्द्रीयकृत निगरानी उपकरण प्रदान किये जाने तथा सलाहकार सेवा द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय को आवश्यकतानुसार सलाहकार सेवाएं प्रदान किया जाना है। क्र मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का क्रियान्वयन किया गया तथा 9 विभागों की 9 योजनाओं को मुख्यमंत्री डै८ाबोर्ड परियोजना में जोड़ा गया। क्र समस्त योजनाओं की विस्तृत आधारों पर समेकित समीक्षा का प्रावधान किया गया।	5633
3.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित	100000	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना एवं रोजगार करने हेतु निवेशकों को	वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में रू. 41.08 करोड़ लागत के 9 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये गए। जिसमें 2059 रोजगार प्रस्तावित है। निवेशकों को रु.	43000

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
		करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना		आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	96.7 लाख का अनुदान वितरीत किया गया। इस अवधि में 1856 राजगार प्रदान किये गये। निवेश प्रोत्साहन हेतु राज्य प्रतिनिधिमंडल की अमेरिका यात्रा- आउटरीच मिशन हेतु सीएसआईडीसी को आवश्यक सहयोग दिया गया। प्रोफेसर यी शी चांग, नेशनल टिंगसिंग हुआ यूनिवर्सिटी, ताइवान द्वारा 'छत्तीसगढ़ डिजिटल विनिर्माण हब' के आतिथ्य में सेमीनार आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली से संबद्ध प,लिसी लैब की स्थापना के लिए एमओयू किया गया।	43000
4.	स्वान परियोजना	छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालयों को जोड़ने हेतु सूचना तंत्र का निर्माण	180000	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर 1450 कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। 150 स्थलों पर मौजूदा सी.जी.स्वान का संचालन और रखरखाव, मौजूदा उपकरणों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध, वीडियो क,न्फ्रेंसिंग 809 सत्र	208628
5.	ई-जिला परियोजना	शासन की प्रमुख जी.2सी. सेवाएँ, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु सॉफ्टवेयर एवं अधोसंरचना का विकास	70000	विभागों को जी.2सी. नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करना	वर्ष 2019-20 में लगभग 28.60 लाख आवेदन प्राप्त किये गए। जिनमें से 27 लाख आवेदनों का निराकरण किया गया है।	126200

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
6.	कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर संस्थान	राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना	24480	एक सशक्त इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर की स्थापना	स्टार्टअप द्वारा कुल 707 प्रत्यक्ष तथा 1090 अप्रत्यक्ष रोजगार नवीन तकनीक का संवर्धन एवं उपयोग शिक्षित युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना।	44638
7.	नागरिक संबंध केन्द्र योजना	शासन की जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन की हितग्राहियों की प्रतिक्रिया के आधार पर समीक्षा	30000	एक कॉल सेंटर की स्थापना एवं समस्त हितग्राहियों के समेकित डेटाबेस का विकास कर शासन की महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का 'फीडबैक' लेना	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लंबित भुगतान का देयकों का भुगतान किया गया है एवं परियोजना का संचालन अभी नहीं हो रहा है।	12000
8.	सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फार इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य के प्रमुख अधोसंरचना निर्माण की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी एवं समीक्षा	13607	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्राजेक्ट्स की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं मॉनिटरिंग टीम की स्थापना	क्र लोक निमाण विभाग की 11, अटल नगर नया रायपर विकास प्राधिकरण की 2 एवं छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की 4 परियोजनाओं का सी.पी.एम. एस. के साथ ऑटोमेशन किया गया। क्र सी.एस.पी.डी.सी.एल. एवं सी.एस.पी.टी.सी.एल. विभागों में संचालित वित्तीय प्रणाली एस.ए.पी. का सी. पी.एम.एस. के साथ एकीकरण का कार्य किया गया है । क्र सिस्टम के उचित संचालन हेतु उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदाय दिया गया है।	26353

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
					क्र विभाग में कार्यरत अधिकारियों को सॉफ्टवेयर संचालन में सहायता एवं आवश्यक समन्वयन हेतु फेसिलिटि मैनेजमेट सपोर्ट का प्रावधान किया गया। क्र सीपीएमएस के तकनीकी संचालन हेतु परियोजना-केंद्र में दो सदस्यीय ऑपरेशन सपोर्ट यूनिट उपलबध करवाये जा गये है। क्र इस प्रणाली के अंतर्गत विभागों की परियोजनाओं से संबंधित प्रत्येक स्तर पर डैशबोर्ड एवं एमआईएस का प्रावधान किया गया है।	
9.	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	313800	विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हुत स्टेट डाटा सेंटर एवं क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	1. वितीय वर्ष 2019-20 में लगभग 175 से अधिक वेबसाइटों एवं एप्लीकेशन जो कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित एवं संधारित की जाती है उनका सफलतापूर्वक होस्टिंग प्रदान करना।	94700

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
					2. वितीय वर्ष 2019-20 में स्टेट डेटा सेंटर में लगभग 50 रैक स्थापित हैं जिसका संचालन एवं संधारण का सफलतापूर्वक स्टेट डेटा सेंटर से किया जा रहा है। 3. विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हेतु स्टेट डाटा सेंटर एवं क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु नवीन स्टेट डेटा सेंटर की विस्तृत कार्य योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा हैं।	
10.	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना	ग्रामों में नागरिकों को ई-गवर्नेंस एवं ई-भुगतान की सेवाएँ प्रदान करना	30000	सामान्य सेवा केन्द्रों का संचालन करना	सामान्य सेवा केन्द्र 2.0 परियोजना अंतर्गत राज्य के 10971 ग्राम पंचायतों में से 10200 ग्राम पंचायतों को परियोजना में सम्मिलित किया जाकर ग्रामीण नागरिको को जनोपयोगी सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।	0
11.	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन	ई-गवर्नेंस कार्यो के लिए जिला स्तर पर संचालन हेतु अमला उपलब्ध कराना	16079	27 जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन करना	1. जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन की म,निटरिंग एवं जी.2सी. सेवाओं की विभिन्न सेवा श्रेणियों में ट्रांजेक्शन की संख्या की रिपोर्ट 2. सेवाओं की प्रदायगी की गुणवत्ता के स्तर की मॉनिटरिंग 3. किसी भी प्रकार के तकनीकी सहायता हेतु हेल्पडेस्क के साथ समन्वय।	16079

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
					4. जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु समन्वय 5. तकनीकी अधोसंरचना के आवश्यक रख-रखाव एवं कनेक्टिविटी की समीक्षा एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना	
12.	वाई-फाई सिटी की योजना	नागरिकों को सर्वाजनिक स्थलों पर नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना	2600	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में 19 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किया गया। संचालन एवं संधारण किया जा रहा है।	2600
13.	विशिष्ट पहचान (आधार) परियोजना	राज्य में आधार योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन करना	12000	राज्य के आधार इनरोलमेंट एजेंसी के रूप में चिप्स को तथा पंजीयक के रूप में इ.सू.प्रौ. विभाग को कार्य करने हेतु सक्षम करना	विशिष्ट पहचान परियोजना अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण यू.आई.डी.ए.आई. एवं चिप्स का अनुबंध निष्पादित किया गया है जिसके अनुरूप राज्य की विभिन्न हितग्राही मुलक परियोजनाओं में ए.यू.ए सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।	0
14.	भारत नेट परियोजना	राज्य में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क का विस्तार करना	78300	ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना	1. भारतनेट फेज 2 के अंतर्गत राज्य नेटवर्क ऑपरेशन केन्द्र (एस.एन.ओ.सी.) की स्थापना 2. 24 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कलेक्टिविटी का विस्तार	0

निष्पादन बजट वर्ष 2019–20

विभाग– इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष– सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019–20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ	
					भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
15.	छत्तीसगढ़ स्टेट स्पासियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य हेतु ऑनलाईन बेव जीआईएस प्लेटफार्म विकसित करना	8605	विभागों को जीआईएस प्लेटफार्म पर ऑनलाईन प्रदान करना	विस्तृत परियोजना पत्रक (डी.पी.आर) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय सहमति हेतु लंबित है।	0

₹ में

टिप्पणियां
8

₹ में

टिप्पणियां
8

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं सलाहकार सेवा परियोजना को दिनांक 01/06/2019 से बंद किये जाने हेतु आदेशित किया जा चुका है।

₹ में

टिप्पणियां
8

पुनर्विनियोजना प्रस्ताव अंतर्गत राशि रू. 2.90 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त हुआ है।

प्रथम अनुपूरक बजट अंतर्गत राशि रू. 8.11 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त हुआ है।

₹ में

टिप्पणियां
8
पुनर्विनियोजना प्रस्ताव अंतर्गत राशि रू. 2.59 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त हुआ है।
पुनर्विनियोजना प्रस्ताव अंतर्गत राशि रू. 1.34 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त हुआ है।

₹ में

टिप्पणियां
8

₹ में

टिप्पणियां
8

₹ में

टिप्पणियां
8

₹ में

टिप्पणियां
8
विस्तृत परियोजना पत्रक (डी.पी.आर) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय सहमति हेतु लंबित है।